ACHIEVERS IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

FOR BPSC EXAMINATION

HINDI

DATE

26/07/2023

+91 8434931877, +91 7250667974

www.achieversiaspatna.co.in

New Patliputra Colony, Road No. 4A, Near Tennis Court, Patna-13

THE HINDU 26.07-2023 National

विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई।

भारत समूह चाहता है कि पीएम मोदी मणिपुर में बोलें। इसेमजबूर करने के लिए वे लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं।

मानसून सत्र के सिर्फ 13 दिन बचे हैं, अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने में स्पीकर को 10 दिन तक का समय लग सकता है। इसकेअलावा अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदन में न्यूनतम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसमुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के सदस्यों से चर्चा की। उन्होंने सभी सांसदों को अब से सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है।

इस बीच मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों को पत्र लिखकर कहा कि सरकार मणिपुर पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है और सहयोग चाहती है।

मोदी ने इंडिया के नाम पर गुटबाजी पर प्रहार किया

पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मौजूदा विपक्ष को देश का अब तक का सबसे 'दिशाहीन' विपक्ष बताया और यहां तक कि 'इंडियन मुजाहिदीन' जैसे संगठनों की भी निंदा की. और 'ईस्ट इंडिया कंपनी' के नाम में भारत था, लेकिन इससे किसी को भी उनके वास्तविक उद्देश्य के बारे में पता नहीं चला।

बाली में संबंधों पर सहमति बनी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल बाली में अपनी बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर "आम सहमति" पर पहुंचे, चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में एनएसए अजीत डोभाल और उनके समकक्ष वांग यी की ब्रिक्स एनएसए बैठक के मौके पर मुलाकात के बाद कहा गया। जोहान्सबर्ग।

डोभाल वांग की बैठक पर भारतीय बयान में चीन के दावे का कोई संदर्भ नहीं था और इसके बजाय वास्तविक रेखा (एलएसी) पर जारी गतिरोध पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसके बारे में श्री डोभाल ने कहा था कि इसने संबंधों के "सार्वजनिक और राजनीतिक आधार" को नष्ट कर दिया है।

सीमा पर टकराव के बाद से पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात नहीं की है। दोनों नेताओं ने एकमात्र बार जी 20 बाली मुलाकात के दौरान गाला समारोह के दौरान बात की थी, जहां उन्होंने कुछ मिनट तक बात की थी। चीनी पक्ष के बयान में इसी बैठक का जिक्र है.

मणिपुर ने इंटरनेट प्रतिबंध थोड़ा हटाया

83 दिन के प्रतिबंध के बाद मणिपुर सरकार। सख्तप्रतिबंधों के बावजूद मंगलवार को इंटरनेट पर प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दी गई।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के फैलने की आशंका के कारण मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध रहेगा।

प्रतिबंध की शर्तों में वाईफाई और वीपीएन के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है; सभी सोशल मीडिया एप्लिकेशन को हटाना। किसी नेटवर्क के लिए "द्वितीयक" उपयोगकर्ताओं के लिए शपथ पत्र भरने की आवश्यकता; और उपयोगकर्ताओं को" भौतिक निगरानी "के अधीन किया जा रहा है।

मणिपुर इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) का कहना है कि वाईफाई प्रतिबंध और अन्य धाराएं अव्यावहारिक हैं।

कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का मानना है कि इंटरनेट प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा रखी गई शर्तें लागू करना कठिन होगा और कई बार अव्यावहारिक भी होंगी।

उदाहरण के लिए: वाईफाई पर प्रतिबंध पूरी तरह से अव्यावहारिक है क्योंकि उपयोगकर्ता केवल वाईफाई चालू कर सकते हैं।

उपयोगकर्ताओं पर नियंत्रण रखना जैसे कि उपकरणों से वीपीएन को हटा दिया जाना और इसके प्रत्येक उपयोगकर्ता से जिम्मेदारी लेना कुछ ऐसा है जिसे नियंत्रित करना कठिन नहीं है।

BJP memners among 19 held in attacking CMs office in Meghalaya .

पुलिस ने सोमवार और मंगलवार को तुरा में मेघालय के मुख्यमंत्री सचिवालय पर हमला करने के आरोप में भाजपा महिला मोर्चा की दो प्रमुखों सहित लगभग 19 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

सोमवार को सीएम कोनार्ड के संगमा मणिपुर की शीतकालीन राजधानी पर चर्चा के लिए स्थानीय नेताओं के साथ एक बैठक में भाग ले रहे थे, तभी एक भीड़ ने सीएम सचिवालय को घेर लिया और पथराव किया।

हमले में मेघालय पुलिस के दस जवान, सीआरपीएफ के सात जवान और एक महिला होम गार्ड स्वयंसेवक घायल हो गए।

मेघालय के डीजीपी ने बाद में कहा कि यह सुनियोजित साजिश थी और इसमें "कुछ राजनीतिक संबद्धता" वाले कुछ पूर्व पुलिसकर्मी शामिल थे।

स्थानीय संगठन चाहते हैं कि तुरा मेघालय की शीतकालीन राजधानी बने। इसकेअलावा नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण का मुद्दा भी मेघालय में एक बड़ा मुद्दा है।

मिजोरम के मुख्यमंत्री कुकी-ज़ो लोगों के लिए आइज़वाल में एकजुटता मार्च में शामिल हुए।

राज्य की राजधानी आइज़वाल में एनएफओ समन्वय समिति (एनसीसी) द्वारा आयोजित "एकजुटता मार्च" में सीएम ज़ोरमथांगा और कई विधायकों के साथ हजारों पुरुष महिलाओं ने भाग लिया। यहमार्च हिंसा प्रभावित कुकी-ज़ो आदिवासी समूह के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए था।

प्रतिभागियों ने आदिवासी महिलाओं पर "क्रूर हमले" के लिए केंद्र और राज्य सरकार की निंदा की। उन्होंनेपीएम मोदी की 'चुप्पी' की आलोचना की और मणिपुर सरकार को 'पूरी तरह विफल' बताया।

मिजोरम की अधिकांश आबादी जातीय रूप से कुकी ज़ो जनजातियों के करीब है।

लोकसभा ने विवादास्पद जैव विविधता विधेयक पारित किया।

जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

- पंजीकृत आयुष चिकित्सा व्यवसायी को जैविक संसाधनों तक पहुँचने से पहले जैव विविधता बोर्डों को सूचित करने से छूट देना चाहता है।
- इसका उद्देश्य अनुपालन बोझ को कम करना, निवेश को बढ़ावा देना और पेटेंट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना भी है।

राष्ट्रपति ने कार्यालय में एक वर्ष पूरा करने पर राष्ट्रपति भवन में जनजातीय कला दीर्घा का उद्घाटन किया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यालय में एक वर्ष पूरा होने पर मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में एक नई गैलरी "जनजातीय दर्पण" का उद्घाटन किया, जो ट्राइबल, कला, संस्कृति और जड़ी-बूटियों को समर्पित एक अनूठी गैलरी है।

गैली को संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय इंडियारा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स (आईजीएनसीए) द्वारा विकसित किया गया था, यह आदिवासी जीवन और कला के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है।

IMF भारत का विकास अनुमान थोड़ा बढ़ाकर 6.1% कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ ने मंगलवार को भारत के लिए अपनी विकास दर को बढ़ाकर 6.1% कर दिया। अप्रैलमें इसका पूर्वानुमान 5.9% था। इसकेपीछे उसने "अपेक्षा से अधिक मजबूत विकास की गति" का हवाला दिया। विकास का अनुमान. आरबीआई द्वारा 6.5% है.

IIMF: भारत के चावल पर प्रतिबंध से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरी ओलिवर गौरिन्कजस ने मंगलवार को कहा कि कुछ प्रकार के चावल के नाम निर्यात के भारत के कदम का काला सागर यूक्रेन समझौते के निलंबन के समान प्रभाव होगा और वैश्विक खाद्य उत्पादन 10 - 15% बढ़ जाएगा।

भारत ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

CBIC ने 9300 फर्जी जीएसटी खातों, ₹11,000 सीआर आक्रमण का पता लगाया।

CBIC,- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड। जीएसटी संग्रह पर नजर।

CBIC ने फर्जी होने के संदेह वाले 25,000 से अधिक जीएसटी खातों की पहचान की, राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को इसकी जानकारी दी;5775 फर्मों का पंजीकरण निलंबित।

16 मई से 19 जुलाई के बीच सीबीआईसी के विशेष अभियान से 9300 से अधिक फर्जी पंजीकरण की पुष्टि हुई। सीबीआईसी ने लगभग ₹ 10,902 करोड़ की कर चोरी का पता लगाया। जिन पांच राज्यों में 60% संदिग्ध फर्जी खाते हैं, वे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, गुजरात हैं।

दुनिया

इजराइल में नए कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन, डॉक्टरों ने काम बंद रखा।

नेसेट द्वारा न्यायिक सुधार विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को हजारों इजरायली डॉक्टर काम से बाहर चले गए, श्रमिक नेताओं ने आम हड़ताल की और वरिष्ठ न्यायाधीश विदेश यात्रा से घर चले गए।

चार प्रमुख इज़रायली अख़बारों ने अपने पहले पन्ने को काली स्याही से ढक दिया और नीचे केवल एक पंक्ति लिखी "इज़राइल लोकतंत्र के लिए एक काला दिन"।

तेल अवीव और येरुशलम में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. गुस्साए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी और बल प्रयोग करना पड़ा.

चीन ने किन गैंग को हटा दिया, वांग यी फिर विदेश मंत्री बने।

चीन के नेता शी जिनपिंग ने किन गैंग को विदेश मंत्री पद से हटा दिया और उनके पूर्ववर्ती वांग यी को कुछ समय के लिए पीएम पद पर बहाल कर दिया गया है।

किन गैंग कई दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों से नदारद है। विदेश मंत्री के रूप में यह उनके कार्यकाल का 7वां महीना था। पर्यवेक्षकों ने उन्हें हटाने के स्पष्टीकरण के रूप में स्वास्थ्य और राजनीतिक दोनों कारणों का हवाला दिया है।

Qin gang and Wang yi

वकील का कहना है कि इमरान को अवमानना के नए आरोपों का सामना करना पड़ेगा।

पाकिस्तान चुनाव निगरानी निकाय ने मंगलवार को कहा कि वह पिछले साल अपने अधिकारी का सार्वजनिक रूप से अपमान करने के आरोप में देश के पूर्व पीएम इमरान खान पर अगले हफ्ते आरोप लगाएगा।

इमरान खान ने 2022 में चुनाव निकाय प्रमुख सिकंदर राजा को पीएम शाहबाज शरीफ का "कार्मिक सेवक" कहा है।

श्री खान पर 150 से अधिक कानूनी मामले दर्ज किये गये हैं।

अनिश्चितता बनी रहती है; सांचेज अंतरिम पीएम हैं.

स्पेन के वर्तमान प्रधान मंत्री को स्पेन के राजा द्वारा नए प्रधान मंत्री के चुने जाने तक अंतरिम प्रधान मंत्री के रूप में मंजूरी दे दी गई है।

चुनाव नतीजों में त्रिशंकु संसद दिखाई दे रही है और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है।

यदि दोनों में से कोई भी समूह छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने और बहुमत साबित करने में सक्षम होगा। उस समूह के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा अन्यथा स्पेन को दोबारा चुनाव कराना पड़ सकता है।

चीन, रूस. उत्तर कोरिया में प्रतिनिधि भेजने के लिए।

1950-53 के कोरियाई युद्ध में लड़ाई रोकने वाले युद्धविराम की 70वीं वर्षगांठ इस सप्ताह उत्तर कोरिया में मनाई जाएगी। चीन और रूस दोनों इस अवसर पर सरकारी प्रतिनिधि भेज रहे हैं।

कोरियाई युद्ध में सोवियत संघ और चीन ने भी उत्तर कोरिया के लिए लड़ाई लड़ी थी, जबकि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के लिए लड़ाई लड़ी थी। वर्तमान स्थिति में अभी भी वही विभाजन दिखता है।

North Korea has been close to Russia and china since it's inception

सम्पादकीय -1

स्वागत हो रहा है

मानवचुनौतीअध्ययनके लिए मजबूतसंस्थागततंत्रस्थापितकिया जाना चाहिए।

संपादकीय के बारे में:

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने नियंत्रित मानव संक्रमण अध्ययन (सीएचआईएस) को मंजूरी दे दी है। इससे वैक्सीन सत्यापन, अपेक्षाकृत कम प्रयास में नई दवा के विकास में काफी मदद मिलेगी।

सीएचआईएस के बारे में:

सीएचआईएस के तहत स्वस्थ स्वयंसेवकों को जानबूझकर रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं इन्ना के अत्यधिक नियंत्रित और निगरानी वाले वातावरण से अवगत कराया जाता है। इससे अपेक्षाकृत कम लागत, समय और प्रयास में टीके और दवा की प्रभावकारिता स्थापित करने में मदद मिलेगी। दुनिया भर में CHOS ने टाइफाइड और कोलेरा जैसी बीमारी का तेजी से टीका बनाने में मदद की है। यहां तक कि CoVid वैक्सीन के उत्पादन के दौरान भी कुछ कंपनियों द्वारा CHIS परीक्षणों का उपयोग किया गया था।

CHIS : से संबंधित चुनौतियाँ:

शोषण, मौद्रिक मुआवज़े के मुद्दे आदि जैसी नैतिक चुनौतियाँ बहुत उच्च स्तर की हैं। इनमेंदुस्साहस की गुंजाइश बहुत अधिक होती है.

साथ ही एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और मजबूत प्रणाली, वैज्ञानिकों, कंपनियों के साथ सहयोग उच्च है। भारत को सुरक्षित और प्रभावी उपचार के साथ बीमारियों का अध्ययन करने के लिए केवल सीएचआईएस का उपयोग करना चाहिए। सीमित चिकित्सा हस्तक्षेप के साथ नवीन रोगाणुओं/बीमारी का अध्ययन करने के लिए सीएचआईएस का उपयोग तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि भारतीय वैज्ञानिक विशेषज्ञता हासिल नहीं कर लेते, और मजबूत संस्थागत संरचनाएं और तंत्र स्थापित नहीं हो जाते।

संपादकीय -2

खतरनाक ओवरहाल

न्यायपालिकाको कमजोर करनेके बाद इजराइलऔर अधिक कमजोरऔर सत्तावादी होजाएगा

संपादकीय के बारे में:

द. इज़राइल में न्यायिक सुधार पर नए कानून के बारे में संपादकीय वार्ता। यह इस सोमवार को बहुमत से पारित विवादास्पद न्यायिक ओवरहाल विधेयक के बारे में बात करता है। इसमें इजराइल और फिलिस्तीन पर भी इसके असर की बात कही गई है.

न्यायिक ओवरहाल बिल के बारे में:

हाल ही में पारित न्यायिक सुधार विधेयक सरकारी निर्णयों या सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायपालिका समीक्षा को प्रतिबंधित करता है। अब कोई भी अधिकारी सरकार के किसी भी "अनुचित" निर्णय पर रोक नहीं लगा सकेगा। विधेयक को 120 सदस्यीय नेसेट में 64 के बहुमत से पारित किया गया।

इसका वेस्ट बैंक, फ़िलिस्तीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

यह वर्तमान सरकार को वेस्ट बैंक में वह करने का अवसर देगा जो वे करना चाहते हैं, इसका अर्थ है वेस्ट बैंक में और अधिक लोगों को बसाना। औरजो लोग इस कदम के ख़िलाफ़ हैं उन्हें सज़ा दे रहे हैं.इज़राइल के पास उन लोगों के लिए दो नियम हैं जो मुख्य भूमि इज़राइल में रहते हैं और उन लोगों के लिए जो वेस्ट बैंक जैसे कब्जे वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं। इजराइलऔर फिलिस्तीन के बीच तनाव और बढ़ेगा.

श्री नेतन्याहू भले ही नेसेट के माध्यम से विधेयक पारित करने में सक्षम हो गए हों लेकिन इससे इज़राइल और भी कमजोर हो गया है।